



जल जीवन मशिन (शहरी)



जल जीवन मिशन (शहरी)

परिचय

- इसकी घोषणा **बजट 2021-22** में की गई थी।
- सभी **4,378** वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से सभी घरों में जल की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिये।
- यह वर्ष **2019** में शुरू की गई केंद्र की ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना (जल जीवन मिशन) के अनुरूप है।

उद्देश्य

- नल और सीवर कनेक्शन तक पहुँच सुनिश्चित सुरक्षित करना
- जल निकायों का नवीनीकरण
- जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करना
- **500** अमृत (AMRUT) शहरों में सीवेज/सेप्टेज प्रबंधन का कवरेज प्रदान करना
- सतत् विकास लक्ष्य **6** (सभी के लिये स्वच्छ जल और स्वच्छता) को पूरा करना

केंद्र सरकार द्वारा वित्तीयन

- केंद्रशासित राज्यों के लिये: **100%**
- पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिये: **90%**
- अन्य राज्यों के लिये:
 - ▶ 1 लाख से कम आबादी वाले शहर: **50%**
 - ▶ 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर: **33.3%**
 - ▶ 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर : **25%**

नोडल मंत्रालय

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

विशेषताएँ

- **पेय जल सर्वेक्षण**-समान वितरण के लिये सर्वेक्षण
- शहरी स्थानीय निकायों की मजबूती पर विशेष जोर
- दोहरी पाइपिंग प्रणाली को बढ़ावा देना
- पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल को बढ़ावा देना
- जल के लिये एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन
- जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान।

परिणाम आधारित वित्तीयन

- परियोजनाओं के लिये सरकार की ओर से वित्तपोषण **20:40:40** की तीन किस्तों में किया जाएगा।



और पढ़ें...

प्रतस्पर्द्धा (संशोधन) वधियक, 2022

प्रलिमिस के लिये:

CCI, प्रतस्पर्द्धा अधिनियम 2002, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)।

मेन्स के लिये:

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002](#) में संशोधन करने वाला विधायक [लोकसभा](#) में पेश किया गया ।

संशोधन की आवश्यकता:

- **नयी पीढ़ी का बाज़ार:**
 - तकनीकी प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कीमत एवं अन्य कारकों के बढ़ते महत्त्व के कारण बाज़ार की गतिशीलता तेज़ी से बदली है, बाज़ार की प्रतस्पर्द्धा को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिये ये संशोधन अपरहार्य हो गए थे ।
- **अधग्रहण का मद्दा:**
 - अधिनियम की धारा 5 के अनुसार वलिय, अधग्रहण या सामेलन में शामिल पक्षों को केवल परसिंपत्तियां कारोबार के आधार पर संयोजन की गतिविधि के विषय में भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग सूचित करने की आवश्यकता है ।
- **गन जंपिंग:**
 - ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक संयुक्त पक्ष अनुमोदन से पूर्व अधिसूचित लेन-देन बंद कर देते हैं अथवा आयोग के संज्ञान में लाए बिना लेन-देन की प्रक्रिया का समापन करते हैं ।
- **हब-एंड-स्पोक कार्टेल:**
 - हब-एंड-स्पोक व्यवस्था एक प्रकार का व्यापारिक गुट है जिसमें ऊर्ध्वाधर रूप से संबंधित हतिधारक एक हब के रूप में कार्य करते हैं और आपूर्तिकर्त्ताओं या खुदरा विक्रेताओं पर क़ैतजि प्रतर्बिध लगाते हैं ।
 - वर्तमान में प्रतस्पर्द्धा-वर्षिधी समझौतों पर प्रतर्बिध केवल समान व्यापार वाली संस्थाओं को शामिल करता है जो प्रतस्पर्द्धा-वर्षिधी गतिविधियों में संलग्न हैं ।
 - यह वितरकों और आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा ऊर्ध्वाधर शृंखला के विभिन्न स्तरों पर संचालित हब-एंड-स्पोक कार्टेल की उपेक्षा करता है ।

प्रस्तावित संशोधन:

- **सौदे के मूल्य की अवसीमा:**
 - नए विधायक में सौदे के मूल्य की अवसीमा का प्रावधान भी प्रस्तावित है ।
 - इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी लेन-देन के विषय में आयोग को सूचित करना अनिवार्य होगा यदि दोनों पक्षों में से किसी का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन है ।
- **पर्याप्त व्यवसाय संचालन:**
 - आयोग किसी उद्यम के भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हेतु आकलन और आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिये विनियम तैयार करेगा ।
 - यह आयोग के समीक्षा तंत्र को सशक्त करेगा, विशेष रूप से डिजिटल और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में , जिनमें से अधिकांश की पहले रिपोर्टिंग नहीं की गई थी, क्योंकि ये परसिंपत्तियां कारोबार मूल्य क्षेत्राधिकार की सीमा को पूरा नहीं करते थे ।
- **संयोजन की गति को तीव्र करना:**
 - किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिये जो एक संयोजन निष्पादित करना चाहता है, उन्हें इस विषय में आयोग को सूचित करना होगा ।
 - पहले आयोग को संयोजन को मंजूरी प्रदान करने के लिये 210 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित थी, जिसके बाद यह स्वतः स्वीकृत हो जाता था ।
 - नए संशोधन ने समय सीमा को 210 कार्य दिवसों से घटाकर केवल 150 कार्य दिवसों और 30 दिनों की वसतिार अवधि को निर्धारित कर दिया है ।
 - यह संयोजनों की मंजूरी में तेज़ी लाएगा और आयोग के साथ संयोजन-पूर्व परामर्श के महत्त्व को बढ़ावा देगा ।
- **गन जंपिंग:**
 - पहले गन-जंपिंग के लिये जुरमाना संपत्तियां कारोबार का कुल 1% था जिससे अब सौदे के मूल्य का 1% किये जाने का प्रस्ताव है ।
- **खुले बाज़ार में खरीदारी की छूट:**
 - यह आयोग को अग्रिम रूप से सूचित करने की आवश्यकता से खुले बाज़ार की खरीद और शेयर बाज़ार के लेन-देन में छूट देने का प्रस्ताव करता है ।
- **हब-एंड-स्पोक कार्टेल:**
 - संशोधन उन संस्थाओं को चिह्नित के लिये 'प्रतस्पर्द्धा-वर्षिधी समझौतों' के दायरे को वसितृत करता है जो कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, भले ही वे समान व्यापार प्रथाओं में शामिल न हों ।
- **मामलों का निपटान और प्रतर्बिधताएँ:**
 - नया संशोधन ऊर्ध्वाधर समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के निपटान और प्रतर्बिधताओं के लिये एक रूप-रेखा का प्रस्ताव करता है ।
 - ऊर्ध्वाधर समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग के मामले में, महानदिशक (DG) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले दोनों पक्ष प्रतर्बिधता के लिये आवेदन कर सकती हैं ।
 - संशोधन के अनुसार, मामले में सभी हतिधारकों का पक्ष सुनने के बाद प्रतर्बिधता या निपटान के संबंध में आयोग का

नरिणय अपील योग्य नहीं होगा।

■ अन्य प्रमुख संशोधन:

○ उदारता का प्रावधान:

- यह आयोग को आवेदक को दंड की अतिरिक्त छूट देने की अनुमति देता है जो एक असंबंधित बाज़ार में दूसरे कार्टेल की उपस्थिति का खुलासा करता है, बशर्ते सूचना आयोग को कार्टेल के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया राय बनाने में सक्षम बनाती हो।

○ महानदिशक की नयुक्ति:

- केंद्र सरकार के बजाय आयोग द्वारा महानदिशक की नयुक्ति आयोग को अधिक नियंत्रण प्रदान करती है।
 - यह आयोग को अधिक नियंत्रण देता है।

○ जुरमाने के संबंध में दशानरिदेश:

- आयोग विभिन्न प्रतस्पर्द्धा उल्लंघनों के लिये दंड की संख्या के संबंध में दशानरिदेश जारी करेगा।
 - आयोग के आदेश के खिलाफ [राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण \(NCLT\)](#) द्वारा अपील पर सुनवाई के लिये पार्टी को जुरमाना राशिका 25% जमा करना होगा।

आगे की राह

■ नए परिवर्तनों के साथ आयोग को नए युग के बाज़ार के कुछ पहलुओं का प्रबंधन करने एवं इसके संचालन को और अधिक मज़बूत बनाने में सक्षम होना चाहिये।

- प्रस्तावित परिवर्तन नसिंदेह आवश्यक हैं, हालाँकि ये आयोग द्वारा बाद में अधिसूचित नियमों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- इसके अलावा सरकार को यह समझना चाहिये कि बाज़ार की गतिशीलता लगातार बदल रही है, इसलिये कानूनों को नियमिति रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता है।

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग

■ परिचय:

- भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) की स्थापना मार्च, 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिये की गई थी।

- यह मुख्य रूप से बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा-वशिधी प्रथाओं के तीन मुद्दों का अनुसरण करता है:

- प्रतस्पर्द्धा वशिधी समझौते।
- प्रभुत्व का दुरुपयोग।
- संयोजन।

■ उद्देश्य:

- प्रतस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना।
- प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- भारत के बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- नमिनलखिति के माध्यम से मज़बूत प्रतस्पर्द्धा माहौल स्थापति करना:
 - उपभोक्ताओं, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों सहित सभी हतिधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव।

■ संरचना:

- प्रतस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नयुक्ति किया जाता है।
 - आयोग [अर्द्ध-न्यायिक निकाय](#) है जो वैधानिक अधिकारियों को सलाह देता है और अन्य मामलों से भी नपिटता है।
 - अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न. अर्द्ध-न्यायिक निकाय क्या है? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से देश के शासन में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2016)

स्रोत: द हिंदू

प्रलिमिंस के लिये:

वमिन वाहक, INS वकिरांत, INS वकिरमादतिय, INS वशिल, F/A 18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू वमिन ।

मेन्स के लिये :

आंतरकि सुरक्षा के लिये वमिन वाहक का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों ?

भारत के पहले **स्वदेशी वमिन वाहक (IAC)**, **वकिरांत** को तैनात करने से पूर्व अमेरिका की प्रमुख सैन्य उपकरण निर्माता कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना को अपने F/A 18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू वमिन को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है ।





LETHAL ADVANCED AFFORDABLE

F/A-18E/F BLOCK III SUPER HORNET



KEY FEATURES



MULTI-ROLE SUPERIORITY

Capable of tactical strike, aerial reconnaissance, air defense, and maritime roles



CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES

Enhanced computing and data link, advanced cockpit system, signature improvements



LIFECYCLE AFFORDABILITY

Lowest cost per flight hour among all U.S. tactical fighter in production. High mission capability rates



FUTURE READY

Unrivaled growth potential to complement future air wing capabilities

40 Year legacy of
carrier-based operations

1.5M+
Flight hours
since 2008

10k+
Hours
airframe life

400+
Sales
opportunities

700+
F/A-18s
delivered



ADVANTAGE INDIA

■ STATE-OF-THE-ART PRODUCTION FACILITY

World-class manufacturing ecosystem built on Boeing's broad presence in India

■ ADVANCED INDIGENOUS TECHNOLOGY

Scope for technology insertions, maximizing indigenous content

■ "BY INDIA - FOR INDIA" SUSTAINMENT

Lifecycle support in partnership with Indian partners and India's armed forces

F/A18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान की मुख्य विशेषताएँ:

- F/A-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक III दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी-रोल फ्रंटलाइन नौसैनिक लड़ाकू विमान है जो भारतीय नौसेना के वाहक के साथ अद्वितीय और अभिदति क्षमता तथा पूर्ण संगतता प्रदान करता है।
- इसे वाहक संचालन के लिये डिज़ाइन और निर्मित किया गया है और यह [INS विक्रमादित्य](#) तथा [INS विक्रान्त](#) विमान वाहक के साथ पूरी तरह से अनुकूलित है।
- F/A-18 हैंगर में डेक पर और भारतीय नौसेना के विमान वाहक के बेस पर कार्य करने में सक्षम है।
- यह विमान वाहक पर मानवयुक्त और मानव रहित प्रणालियों के मध्य इंटरफेस बढ़ावा देगा।
- सुपर हॉर्नेट का सटीक लैंडिंग मोड सॉफ्टवेयर विशेष रूप से उच्च ग्लाइड स्लोप और गति को बनाए रखते हुए भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य वाहक पर उतरते समय पायलट कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।

- यह पूरणतः स्वचालित और वाहक के ऑप्टिकल लैंडिंग प्रणाली से स्वतंत्र है।
- F/A-18 सुपर हॉर्नेट के सगिल-सीटर (E-Variant) और टू-सीटर (F-Variant) दोनों संस्करण उपलब्ध हैं जो पूरी तरह वाहक डेक द्वारा संचालित हो सकते हैं।
 - टू-सीटर एक संक्षिप्त प्रशिक्षक विमान भी है।

आईएसी विक्रांतः

- परिचयः
 - विक्रांत भारत में अब तक बनाया गया सबसे बड़ा युद्धपोत है, और भारतीय नौसेना के लिये स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित पहला विमानवाहक पोत है।
 - यह भारत को उन राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में शामिल करता है जो इन विशाल, शक्तिशाली युद्धपोतों को डिज़ाइन और उनका निर्माण करने की क्षमता रखते हैं।
 - यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो कंबिंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है।
 - जहाज़ ने समुद्री परीक्षाओं के अपने चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था
- संचालन क्षमताः
 - इसकी अधिकतम डिज़ाइन गति 28 समुद्री मील (लगभग 52 कमी/घंटा) और 7500 NM की सहनशक्ति है।
 - इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक होगा, जिसमें युद्धपोत मृगि-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) शामिल हैं।
 - शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी (STOBAR) नामक एयरक्राफ्ट-ऑपरेशन मोड का उपयोग करते हुए IAC विमान को लॉन्च करने के लिये स्की-जंप तथा एयरक्राफ्ट पर उनकी पुनर्प्राप्ति के लिये तीन 'अरेस्टर वायर' के सेट लैस हैं।
 - यह एक कोणीय स्की-जंप के साथ शॉर्ट टेक-ऑफ लेकिन अरेस्ट रिकवरी या STOBAR तंत्र पर काम करता है।
- महत्वः
 - यह हवाई वर्चस्व अभियानों के संचालन के लिये अपने घरेलू समुद्री तटों से दूर यात्रा करने की नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा।
 - इसे एक "" नौसेना माना जाता है, जो एक ऐसी नौसेना है जो उच्च समुद्रों में एक राष्ट्र की ताकत और शक्ति को प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखती है।

भारत में विक्रांत निर्माण का महत्त्वः

- वर्तमान में केवल पाँच या छह देशों के पास विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत अब इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है।
 - विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत ने दुनिया के सबसे उन्नत और जटिल युद्धपोतों में से एक माने जाने वाले निर्माण की क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया है।
- भारत के पास पहले भी विमानवाहक पोत ब्रिटिश या रूस से आयातित थे। 'INS विक्रमादित्य', जिसे 2013 में कमीशन किया गया था और जो वर्तमान में नौसेना का एकमात्र विमानवाहक पोत है, सोवियत-रूसी युद्धपोत 'एडमिरल गोरशकोव' का भारतीय संस्करण है।
- भारत के पहले के दो वाहक, 'INS विक्रांत' और 'INS वरिष्ठ' मूल रूप से ब्रिटिश निर्मित 'एचएमएस हरक्यूलस' और 'एचएमएस हर्मीस' थे। इन दोनों युद्धपोतों को क्रमशः वर्ष 1961 और 1987 में नौसेना में शामिल किया गया था।

नए युद्धपोत IAC-1 का नाम 'INS विक्रांत' रखा जाएगाः

- 'INS विक्रांत' नाम मूल रूप से भारत के बहुचर्चित पहले विमानवाहक पोत से संबंधित था, जो 1997 में सेवामुक्त होने से पहले कई दशकों की सेवा में राष्ट्रीय गौरव था।
 - मूल 'विक्रांत' 19,500 टन वजन का एक मैजस्टिक-क्लास युद्धपोत, जिसे वर्ष 1961 में यूनाइटेड किंगडम से अधिग्रहीत किया गया था, ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पछिले वर्ष जैसे ही IAC-1 ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया, नौसेना ने "भारत के लिये गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन" बताया क्योंकि समुद्री परीक्षाओं के लिये 'विक्रांत' का पुनर्निर्माण हुआ था।

IACs हेतु भविष्य की योजनाएँः

- नौसेना 2015 से देश के लिये तीसरा विमानवाहक पोत बनाने की मंजूरी मांग रही है, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक (IAC-2) बन जाएगा।
- इस प्रस्तावित वाहक का नाम 'INS विशाल' रखा गया है, जो 65,000 टन का विशाल पोत है, यह IAC -1 और 'INS विक्रमादित्य' दोनों से काफी बड़ा है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्नः

प्रश्नः नमिनलखिति में से कौन सा 'INS अस्त्रधारिणी' का सबसे अच्छा वर्णन है, जो हाल ही में समाचारों में था? (2016)

- (a) उभयचर (एम्फबि) युद्ध जहाज़
- (b) परमाणु संचालित पनडुब्बी
- (c) टारपीडो लॉन्च और रकिवरी पोत
- (d) परमाणु संचालित विमान वाहक

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- INS अस्त्रधारिणी एक स्वदेश निर्मित टारपीडो लॉन्च और रकिवरी पोत है। इसे 6 अक्टूबर, 2015 को कमीशन किया गया था।
- अस्त्रधारिणी का डिज़ाइन नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL), शाफ्ट शिपयार्ड तथा आईआईटी खड़गपुर का एक सहयोगात्मक प्रयास था।
- यह अस्त्रधारिणी के लिये एक उन्नत प्रतस्थापन है जिसे 17 जुलाई, 2015 को बंद कर दिया गया था।
- इसमें कटमरैन के रूप का एक अनूठा डिज़ाइन है जो इसकी बजिली की आवश्यकता को काफी कम करता है और इसे स्वदेशी स्टील के साथ बनाया गया है।
- यह उच्च समुद्री राज्यों में काम कर सकता है और परिक्षणों के दौरान विभिन्न प्रकार के टारपीडो को तैनात करने और पुनर्प्राप्त करने के लिये टारपीडो लॉन्चर्स के साथ एक बड़ा डेक क्षेत्र है।
- जहाज़ में आधुनिक बजिली उत्पादन और वतिरण, नेविगेशन और संचार प्रणाली भी है।
- जहाज़ की 95% प्रणालियाँ [\[?/?/?/?/?/?/?/?\]](#) डिज़ाइन की हैं, इस प्रकार यह 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण लिये नौसेना के नरितर प्रयास को प्रदर्शित करता है।
- INS अस्त्रधारिणी का उपयोग डीआरडीओ की नौसेना प्रणाली प्रयोगशाला, एनएसटीएल द्वारा पानी के नीचे हथियारों और प्रणालियों के तकनीकी परीक्षण के लिये विकसित किया जाएगा। **अतः विकल्प (C) सही है।**

प्रश्न : एस-400 वायु रक्षा प्रणाली, दुनिया में वर्तमान में उपलब्ध किसी भी अन्य प्रणाली से तकनीकी रूप से कैसे बेहतर है? (मुख्य परीक्षा, 2021)

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

सर्वोच्च न्यायालय की संवधान पीठ

प्रलिस के लिये:

भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 145(3), अनुच्छेद 143।

मेन्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय की संवधान पीठ।

चर्चा में क्यों?

भारत के 49वें [मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आश्वासन दिया कि [सर्वोच्च न्यायालय](#) में वर्ष भर में कम से कम एक संवधान पीठ कार्य करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की संवधानिक पीठ:

- **परचिय:**
 - संवधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें पाँच या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं।
 - हालाँकि इन पीठों का गठन नियमित तौर पर नहीं होता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिकांश मामलों की सुनवाई और नरिणय दो न्यायाधीशों (जन्हें डिवीजन बेंच कहा जाता है) और कभी-कभी तीन सदस्यों की पीठ द्वारा किया जाता है।
- **संवधानिक पीठ गठन हेतु अपरहार्य परस्थितियाँ:**
 - अनुच्छेद 145(3):

- अनुच्छेद 145(3) में प्रावधान है कि "इस संविधान की व्याख्या के रूप में या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले के नरिणयन के उद्देश्य से शामिल होने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होगी"।

◦ **अनुच्छेद 143:**

- जब राष्ट्रपति संविधान के **अनुच्छेद 143** के तहत कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगता है।
- प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास **सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति** है, जसि वह लोक कल्याण के लिये महत्वपूर्ण मानते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय, इन संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देता है। हालाँकि, शीर्ष न्यायालय द्वारा इस तरह की सलाह राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी नहीं** है, न ही यह '**सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून**' है।

◦ **परस्पर वरिधी नरिणयन:**

- जब सर्वोच्च न्यायालय के दो या तीन से अधिक जजों की पीठ ने कानून के एक ही बटु पर **परस्पर वरिधी नरिणय** दिये हों, तो एक **बड़ी पीठ द्वारा कानून की नश्चिति समझ और व्याख्या की आवश्यकता** होती है।
 - अतः संविधान पीठों को जब उपर्युक्त शर्तें मौजूद होती हैं तो **तदर्थ आधार पर स्थापति** किया जाता है और।

CJI द्वारा स्थायी संवैधानिक पीठ की मांग करने के प्रमुख कारण:

- वर्तमान में संविधान पीठों की **स्थापना तदर्थ आधार पर (वर्ष उद्देश्य) के रूप में** की जाती है विशेषकर जब **इनकी आवश्यकता** होती है।
- इसका उद्देश्य न्यायाधीशों को उन मामलों की पहचान करने, सुनने और राहत प्रदान करने में मदद करना है, जनि पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री की लंबी-चौड़ी प्रक्रियाओं के कारण न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई के लिये अपने मामलों को सूचीबद्ध करने में देरी से बचने के लिये वादियों और वकीलों की मदद करना है।
- यह इसलिये भी जरूरी है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में लंबाई मामले वर्ष 2017 के स्तर 55,000 से बढ़कर वर्तमान में 71, 000 से अधिक हो गई है।
 - यह इसके बावजूद है कि अगस्त 2019 में न्यायालय की स्वीकृत न्यायिक शक्ति को बढ़ाकर 34 न्यायाधीशों तक कर दिया गया था।

आगे की राह

- जब तक संवैधानिक बेंच के फैसले स्पष्ट उदाहरण स्थापति नहीं करते हैं और बड़ी संख्या में मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के बनिा लिखित आदेशों के माध्यम से खारजि कर दिया जाता है तो संवैधानिक बेंच के क्षेत्राधिकार के दीर्घकालिक लाभ सीमिति हो सकते हैं।

प्रश्न. हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से कैसे अलग है?(2021)

1. कानून के संबंध में, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है लेकिन भारत में, संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमिति है।
2. भारत में, संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कार्यकारी और न्यायिक निकायों सहित अन्य सभी सरकारी संस्थानों पर वधायी निकाय यानी संसद की सर्वोच्चता होती है। ब्रिटन में संसदीय संप्रभुता है यानी वधायिका किसी भी पछिले कानून को बदल सकती है या नरिस्त कर सकती है और संविधान जैसे किसी लिखित कानून से बाध्य नहीं है। **अतः कथन 1 सही है।**
- भारत में कोई संसद संप्रभुता नहीं है बल्कि संवैधानिक संप्रभुता है और संसद के अधिकार और अधिकार क्षेत्र सीमिति हैं:
 - लिखित संविधान जो राज्य के सभी अंगों पर प्रतबंध लगाता है।
 - संघ और राज्यों के बीच वधायी शक्तियों का वितरण (अनुच्छेद 245-246 और सातवी अनुसूची),
 - न्यायोचित मौलिक अधिकारों की संहिता का समावेश (अनुच्छेद 12-35 और 226), और
 - न्यायिक समीक्षा और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिये सामान्य प्रावधान। न्यायपालिका वधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून या अध्यादेश को शून्य घोषित कर सकती है, यदि उसका कोई प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों में से एक या अधिक का उल्लंघन करता है। **अतः 1 सही है।**
- संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की पीठ होती है जसिमें पाँच या अधिक न्यायाधीश होते हैं।

अतः विकल्प (c) सही है।

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजयि: (2021)

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कसिी भी सेवानवित्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपतकी पूरव अनुमतसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लयि वापस बुलाया जा सकता है ।
2. भारत में एक उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के नरिणय की समीक्षा करने की शक्त है जैसा कसिी सर्वोच्च न्यायालय करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो मैं और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश कसिी भी समय राष्ट्रपतकी पूरव सहमतसे कसिी भी व्यक्तसे नमिनलखिति योग्यताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं:
- जसिने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद पर कार्य कयिा हो । **अतः कथन 1 सही है ।**
- जसिने कसिी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कयिा हो और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नयुक्त के लयि वधिवित अरहता प्राप्त कर चुका हो ।
- कोर्ट ऑफ रकिर्ड होने के कारण उच्च न्यायालय भारत के संवधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने स्वयं के नरिणयों की समीक्षा कर सकता है । इसी तरह अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कसिी भी नरिणय या उसके द्वारा दयि गए आदेश की समीक्षा करने की शक्त होगी **अतः कथन 2 सही है ।**

प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नयुक्त के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायकि नयुक्त आयोग अधनियिम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि । (मुख्य परीक्षा, 2017)

[स्रोत: द हट्टि](#)

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य

प्रलिमिस के लयि:

शुद्ध शून्य उत्सर्जन, राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC) ।

मेन्स के लयि:

शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासलि करने के लयि भारत द्वारा उठाए गए आवश्यक कदम ।

चर्चा में क्यों?

गेटगि इंडयिा टू नेट जीरो की रपिोर्ट के अनुसार, अगर भारत को वर्ष 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो भारत को अब से बड़े पैमाने पर 10.1 ट्रिलियन डॉलर के नविश की आवश्यकता है ।

रपिोर्ट की मुख्य वशैषताएँ:

- नविश:
 - यदशुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को वर्ष 2050 तक पूरा करना है तो भारत द्वारा आवश्यक नविश 13.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा ।
- राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC):

- वर्ष 2015 में निर्धारित **भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** लक्ष्यों को वर्तमान नीतियों के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में जल्दी पूरा किये जाने की संभावना है।
- **अधिक उत्सर्जन:**
 - भारत, वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में चरम पर पहुँच सकता है।
- **लाभ:**
 - वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के संदर्भ में वर्ष 2036 तक वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में 4.7% की वृद्धि होगी और 2047 तक 1.5 मिलियन नए रोजगार सृजित होंगे।
- **सुझाव:**
 - नवीकरणीय ऊर्जा और वदियुतीकरण को बढ़ावा देने के लिये सुझाई गई विभिन्न नीतियाँ सदी के मध्य तक शुद्ध शून्य को संभव बना सकती हैं।
 - वर्ष 2023 तक नए कोयले के उपयोग को समाप्त करना और वर्ष 2040 तक कोयला शक्तिका संक्रमणीय प्रयोग 20वीं शताब्दी के मध्य के करीब शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने के लिये विशेष रूप से प्रभावशाली होगा।

शुद्ध शून्य लक्ष्य:

- इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा।
- बल्कि, यह एक ऐसा देश है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है।
 - इसके अलावा, वनों जैसे अधिकांश कार्बन सिके बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है।
 - जबकि वातावरण से गैसों को हटाने के लिये कार्बन कैपचर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है।
- भारत ने **COP-26 शिखर सम्मेलन** के सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है।

वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- **भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:**
 - भारत द्वारा पेरिस में घोषित किये गए अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, वर्ष 2022 तक के स्तर 175 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट करने को अब वर्ष 2030 तक बढ़ाकर **COP26** में 500 गीगावाट कर दिया है।
 - भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% स्थापित वदियुत् उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की भी घोषणा की है, जो 40% के मौजूदा लक्ष्य को बढ़ाता है, जो पहले ही लगभग हासिल कर लिया गया है।
- **NDC के लक्ष्य:**
 - इनकी पहचान निम्नानुसार की गई है:
 - जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी के रूप में लाइफसाइल फॉर एनवायरनमेंट (LIFE) के लिये जन आंदोलन सहित संरक्षण और संयम की परंपराओं एवं मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के स्वस्थ तथा टिकाऊ तरीके को आगे बढ़ाना।
 - आर्थिक विकास के संबंधित स्तर पर अन्य लोगों द्वारा अपनाए गए मार्ग की तुलना में जलवायु के अनुकूल और स्वच्छ मार्ग को अपनाना।
 - वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।
 - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी वदियुत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना,
 - यह हरित जलवायु कोष (GCF) सहित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय वित्त की मदद से संभव होगा।
 - वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO₂ के बराबर अतिरिक्त कार्बन संचय करना।
 - जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों और स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के लिये विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन करना।
 - आवश्यक संसाधन और संसाधन अंतराल को देखते हुए उपरोक्त शमन एवं अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिये वकिसति देशों से घरेलू तथा नए तथा अतिरिक्त धन जुटाना।
 - भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी के त्वरित प्रसार और ऐसी भावी प्रौद्योगिकियों के लिये संयुक्त सहयोगी अनुसंधान एवं विकास हेतु क्षमता निर्माण, तथा एक घरेलू ढाँचा और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करना।
- **पहल:**
 - **सौर ऊर्जा:**
 - भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा स्थापना पहलों में से एक की शुरुआत की है।
 - चाहे वह वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता प्राप्त कर ले या वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त कर ले,
 - **कार्बन संचय:**
 - **इंडिया क्लाइमेट एक्शन प्लान (ICAP)** देश में शीतलन ज़रूरतों को पूरा करने और शीतलन की मांग को कम करने में मदद करेगा।
 - **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** और **एनरजी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL)** ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE) के तहत कई पहल की हैं।

- प्रतपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के तहत बनाए गए प्रतपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) कोष में हज़ारों करोड़ हैं, जिसका उपयोग जलद ही वनों की कटाई की भरपाई करने और पेड़ों की स्थानिक प्रजातियों को शामिल करने वाले हरित आवरण को बहाल करने के लिये किया जाएगा।
- **हाइड्रोजन ऊर्जा:**
 - भारत ने ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन के लिये हाइड्रोजन ऊर्जा मशिन की भी घोषणा की है।

आगे की राह:

- भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य और अद्यतित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) नश्चित रूप से महत्वाकांक्षी हैं, जो क्विबडि महामारी के बाद इससे उबरने की आवश्यकताओं पर बल दे रहे हैं।
 - हालाँकि ये वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई पर वृद्धिशील प्रगतिके एक सामान्य प्रणाली में समायोजित होते हैं जिसमें पूर्व-औद्योगिक स्तरों से वैश्विक तापन को 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये आवश्यक सामूहिक भावना का अभाव है।
 - इसके अलावा भारत सहित विश्व स्तर पर सीमित अल्पकालिक उत्सर्जन में कमी और महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक जलवायु कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन उपेक्षित है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रलिस:

Q. 'इच्छति राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' शब्द को कभी-कभी समाचारों में कसि संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा की गई प्रतजिज्ञा
- जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये विश्व के देशों द्वारा उल्लिखित कार्य योजना
- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना में सदस्य देशों द्वारा योगदान की गई पूंजी
- सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में दुनिया के देशों द्वारा उल्लिखित कार्य योजना

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- 'इच्छति राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान', UNFCCC के तहत पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिये व्यक्त की गई प्रतबिद्धता को बताता है।
- CoP 21 में दुनिया भर के देशों ने सार्वजनिक रूप से उन कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की, जिन्हें वे अंतरराष्ट्रीय समझौते अंतर्गत क्रियान्वयित करना चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दशा में अगरसर है जो "वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा देता है और इस शताब्दी के उत्तरार्ध में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।" अतः विकल्प (b) सही है।

मेनस:

Q. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पार्टियों के सम्मेलन (CoP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन करें। इस सम्मेलन में भारत द्वारा व्यक्त की गई प्रतबिद्धताएँ क्या हैं? (2021)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस